महिला सामाख्या परियोजना

3358. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिला सामाख्या परियोजना पर इसके आरंभ से लेकर अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है और 31 अक्तूबर, 1993 तक इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में तथा वर्ष 1993-94 के लिए इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कितनी कितनी मात्रा के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं तथा 1993-94, 1994-95 के वर्षों और आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) 31-10-1993 तक महिला समाख्या परियोजना पर खर्च किया गया कुल व्यय 9,77,17,806 रुपये है । व्यय का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है :-

महिला समाख्या सोसाइटी कर्नाटक।	3,35,64,550 रु.
महिला समाख्या सोसाइटी, गुजरात	2,10,64,550 रु.
महिला समाख्या सोसाइटी उत्तर प्रदेश	1,75,00,000 रु.
महिला समता सोसाइटी आन्ध्र प्रदेश	57,70,000 रु.

(ख) 7 वीं योजना अवधि के दौरान वर्ष 1988-89 तथा वर्ष 1989-90 में महिला समाख्या परियोजना परिव्यय 12 करोड़ रु. था । वर्ष 1993-94 में कुल परिव्यय 8.80 करोड़ रु. है ।

(ग) महिला समाख्या परियोजना महिलाओं के लिये एक ऐसा वातावरण सृजित करना चाहती है जिसमें वे ज्ञान तथा सूचना प्राप्त कर सकें ताकि वे जानकारी के साथ अपनी पसन्द बना सकें और ऐसी परिस्थितियां सृजित हों जहां पर महिलाएं स्वयं अपनी गति तथा लय से सीख सकती हों। 7वीं योजना अवधि के दौरान कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात के दस जिले इस परियोजना में शामिल किये गये थे। 8वीं योजना अवधि के दौरान चार राज्यों के 20 जिलों को शामिल करने के लिये इस योजना को अनुमोदित कर दिया गया है। वर्ष 1993-94 तथा वर्ष 1994-95 के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गये हैं ।

संस्कृत भाषा का विकास

3359. **श्री गोपाल सिंहजी सोलंकी :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संस्कृत भाषा को वैकल्पिक भाषा बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और क्या सरकार ने इस भाषा के विकास हेतु विशेषज्ञों के साथ इस विषय पर विचार विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी प्रयोग के प्रयोजनार्थ संस्कृत को तीसरी भाषा के रूप में अपनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

OPENING OF KENDRIYA VIDYALAYA IN GUJARAT

3360. **SHRI GOPAL SINGH G. SOLANKI :** Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to open new Kendriya Vidalayas in the

districts of Panchmahal, Surat, Rajkot, Bharuch, Junagadh, Amreli, Kheda and Banaskantha of Gujarat in the current financial year;

(b) if so, the details of allocations of admissions of each standards; and

(c) what are the number of Kendriya Vidyalayas functioning in each district in Gujarat ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) There are 40 Kendriya Vidyalayas at present functioning in Gujarat. There is no system of allocating or opening of Kendriya Vidyalayas on a district-wise or State-wise basis.

देश में बालविकास केन्द्र

3361. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार तथा जिला-वार कितने बाल विकास केन्द्र कार्यरत हैं और इनकी स्थापना कब से हुई है;

(ख) गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र द्वारा संचालित केन्द्रों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है;

(ग) इन केन्द्रों को सरकार द्वारा प्रति वर्ष कितनी धनराशि आवंटित की जाती है;

(घ) क्या सरकार नये बाल विकास केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासव राजेश्वरी) : (क) वर्ष 1975-76 में समेकित बाल विकास सेवा योजना के आरम्भ होने से 31-3-1993 तक देश में कुल 3066 आई सी डी एस परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिनमें राज्य क्षेत्र की 195 परियोजनाएं भी शामिल हैं । इन आई सी डी एस परियोजनाओं की राज्य वार और जिला-वार संख्या अनुपत्र में दी गई है । [देखिए परिशिष्ट 169, अनुपत्र संख्या 68]

(ख) 46 आई सी डी एस परियोजनाओं के अन्तर्गत लगभग 2595 आंगनवाड़ियों में गैर सरकारी संगठन समेकित बाल विकास सेवा योजना चला रहे हैं । गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जा रही आई सी डी एस परियोजनाओं/आंगनवाड़ी केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है । शेष आई सी डी एस परियोजनाएं सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चलाई जा रही हैं ।

(ग) योजना के मापदण्डों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा एक आई सी डी एस परियोजना को चालू रखने हेतु एक वर्ष में औसतन 14.56 लाख रुपए दिए जाते हैं । यह राशि सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले पूरक पोषाहार के अतिरिक्त होती है।

(घ) और (ङ) वर्ष 1993-94 के दौरान 14 राज्यों में 200 नई आई सी डी एस परियोजनाएं स्वीकृत करने का प्रस्ताव है । चालू वर्ष के दौरान प्रस्तावित आई सी डी एस परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-2 में दी गई